



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7710

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45229 वर्ष 2025

रवि शंकर दिवाकर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अल्पना सिंह, मनीष कुमार कश्यप, वीरेन्द्र पाल सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री अल्पना सिंह, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान एजीए श्री अरिमर्दन यादव को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक रवि शंकर दिवाकर की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 172 of 2025, धारा 8/20/29/60, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. अधिनियम), थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उन्हें इसी प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह 19.11.2025 से जेल में बंद हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसी तरह से परिचालित सह-आरोपी अमर सिंह ठाकुर और शिवम कश्यप को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 18.11.2025 और 1.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 38307 और 2025 के 40420 में जमानत पर जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन यह प्रस्तुत किया है कि इसी तरह से परिचालित उपरोक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के प्रकरण में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया प्रकरण, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **रवि शंकर दिवाकर**, जो उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/न ही डरायेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट नहीं दी जाती है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

12 जनवरी, 2026

सुमैरा